कोटद्वार, बुधवार
3 दिसम्बर 2025
वर्ष: 48
अंक: 197 पृष्ठ: 4
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

पथरी में संदिग्ध परिस्थियों में युवक की मौत, हत्या की आशंका

हरिद्वार। धारीवाला गांव में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुची पुलिस को शव कमरे से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शव के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक के गले में पुलिस को निशान मिले हैं। इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र के धारीवाला गांव निवासी 42 वर्षीय सुरेश पुत्र सुखबीर सिंह ने कमरे में संदिग्ध परिस्थियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाइयों ने मामले की सूचना पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि भाइयों ने पहले ही शव को फंदे से नीचे उतारा हुआ था। पुलिस की प्रथम जांच में सामने आया है कि मृतक के चेहरे और गल्ले पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं।

अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया वाहन, युवक की मौत

रुद्रपुर। सोमवार देर रात काशीपुर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में एक युवक और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक का उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, ग्राम सिरसा सिसैया, दातागंज बदायूं यूपी निवासी 23 वर्षीय प्रदीप पुत्र बनवारी सिंह अपने भाइयों के साथ रम्पुरा में किराये पर रहकर विवाह समारोह में काउंटर लगाने का काम करता था। सोमवार रात वह तीनपानी से काउंटर लादकर पिकअप वाहन से काशीपुर की ओर दूसरी बुकिंग पर जा रहा था। सोब्ती होटल के पास चालक वाहन से अचानक नियंत्रण खो बैठा और वाहन डिवाइडर से जा टकराया। हादसे में प्रदीप और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रदीप की मौत की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि हादसा वाहन के अनियंत्रित होने से हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

बुर्का पहनाकर नानकमत्ता ले जाई गईं दो किशोरियां बरामद

रुद्रपुर। सितारगंज की दो किशोरियां को दो युवक बुर्का पहनाकर नानकमत्ता ले गए। दोनों किशोरियां सोमवार सुबह घर से आवासीय विद्यालय के लिए निकली थीं। संदिग्ध स्थिति देखकर स्थानीय लोगों ने पूछताछ की और पुलिस को सूचना दी। मामले में एक किशोरी के पिता ने नानकमत्ता थाने में तहरीर देकर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। सोमवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि स्कूल ड्रेस में दो किशोरियां नानकसागर जलाशय के पास संदिग्ध हालत में हैं और उनके साथ दो युवक भी मौजूद हैं। बताया गया कि किशोरियां वहां एक झोपड़ी में कपड़े बदलने गई थीं। इस दौरान कुछ संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। झोपड़ी स्वामी को धमकाने की स्थिति बनने पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि किशोरियों ने सिर्फ कपड़े बदलने के लिए झोपड़ी का उपयोग करने का अनुरोध किया था। इस्लामनगर, सितारगंज के दो युवकों के साथ होने की सूचना पर विहिप प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उधर, एक किशोरी के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया कि दोनों युवक किशोरियों को बहला–फुसलाकर गंदी नीयत से ले जा रहे थे। परिजनों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने किशोरियों को नानकसागर क्षेत्र से बरामद कर लिया। दोनों युवकों की पहचान की जा चुकी है।

शादी समारोह के दौरान होटल में महिला का लाखों का हार चोरी

देहरादून। पटेलनगर स्थित होटल में चल रहे शादी समारोह में महिला के पर्स में रखा सोने का हार चोरी हो गया। घटना बीते 24 नवंबर की रात हुए शादी समारोह के दौरान की है। महिला की शिकायत पर सोमवार को पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि लता रस्तोगी पत्नी राकेश रस्तोगी, हाल निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला, निकट रामप्यारी स्कूल, मूल निवासी बरेली, यूपी ने तहरीर दी। बताया कि वह बीते 24 नवंबर की रात रिश्तेदारी के शादी समारोह में सहारनपुर रोड स्थित होटल ले अमृतम में मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने 32 ग्राम वजन का रानी का हार पहना हुआ था।

सरदार पटेल की प्रेरणा से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू: धामी

"सरदार@150 यूनिटी मार्च: धामी और राजनाथ सिंह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

देहरादून। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को साधली, बड़ोदरा, गुजरात में सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत आयोजित सरदार गाथा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को समस्त उत्तराखंडवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण से अखंड भारत का सपना साकार किया। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि खेड़ा और बारदोली के किसान आंदोलनों में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र–सेवा के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल ने संवाद, प्रेम, दृढ़ता और निर्भीकता का परिचय देते हुए 562 रियासतों को भारत में मिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री द्वारा सरदार पटेल की प्रेरणा से एक भारत, श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक विधान, एक संविधान के संकल्प को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया। साथ ही सरदार पटेल के जन्म दिवस पर देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर युवाओं को सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में भी एकता यात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने बताया उन्होंने स्वयं चार प्रमुख स्थानों पर एकता यात्रा में प्रतिभाग किया है। एकता यात्रा के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे विषयों से जोड़ने के साथ सहकारिता मेलों का आयोजन कर स्थानीय हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में भी कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया एकता यात्रा के दौरान ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान भी किया गया। विभिन्न गाँवों में सरदार उपवन विकसित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है।

बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रही कंपनी एमडी की हादसे में मौत

रुद्रपुर। अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर कंपनी जा रहीं एमडी की स्कूटी को एक स्कूल बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। पति की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय अनीता चौरसिया अपने पति रामशरन चौरसिया और बच्चों के साथ बालाजीपुरम, तीनपानी डैम क्षेत्र में रहती थीं। पति ने बताया कि रुद्रपुर में उनकी सुपरटेक इंडस्ट्री नाम की कंपनी है, जिसकी एमडी उनकी पत्नी अनीता थीं। मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वह अपनी कंपनी जा रही थीं। करीब नौ बजे जब वह दक्ष चौराहे के पास पहुंचीं, तभी पीछे से आ रही एक स्कूल बस ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बस और स्कूटी को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।

काशी तमिल संगमम में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक

तुरंत एक्शन में आए कमांडो

नई दिल्ली। नमो घाट पर मंगलवार शाम काशी तमिल संगमम् के शुभारंभ के दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। 25 वर्षीय युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जा रहा था, तभी कमांडो ने दबोच लिया। इस दौरान वह ह्यचौबेपुर में काटा जा रहा...ह्न बड़बड़ा रहा था। गाली–गलौज भी कर रहा था। सीपी और एडीशनल सीपी ने पूछताछ के बाद उसे आदमपुर थाने भेज दिया। थाने पहुंचे उसके भाई ने उसे मानसिक रोगी बताया है।

मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य वीवीआईपी थे। तभी एक युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जाने लगा। यह देख कमांडो ने उसे दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। उसकी पहचान चौबेपुर बाजार निवासी जोगेंद्र गुप्ता के रूप में हुई। नशे में धुत युवक लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। थाने पर उसका भाई पहुंचा। बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। इसी तरह बड़बड़ाता रहता है। शराब अधिक पीता है। पुलिस ने युवक के साथ उसके परिवार के बारे में भी ब्योरा जुटाया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक मानसिक बीमार बताया जा रहा है। वह अधिक शराब पीता है। उसे गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

पाकिस्तान के झूठे दावों की खुली पोल

श्रीलंका की मदद की आड़ में खेल रहा गंदा खेल, भारत ने कर दिया बेनकाब

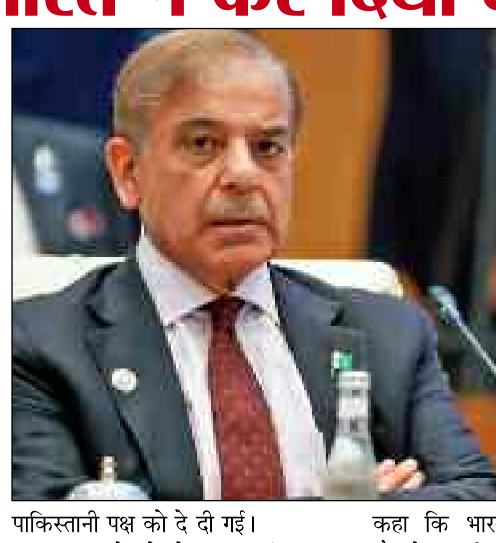

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पाकिस्तान के उस आरोप को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता लेकर जाने वाले पाकिस्तानी विमान को भारतीय एयरस्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी गई।

एमईए ने इस दावे को बेतुका और भारत–विरोधी झूठ फैलाने का नया प्रयास बताया। मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगाई गई सभी बातें बिना आधार हैं।

चार घंटे में मिला क्लियरेंस

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से ओवरफ्लाइट क्लियरेंस का अनुरोध 1 दिसंबर (सोमवार) दोपहर 1 बजे भारत के उच्चायोग (इस्लामाबाद) को मिला था। मानवीय सहायता की तात्कालिकता को देखते हुए यह अनुरोध उसी दिन तेजी से प्रक्रिया में लिया गया। भारत ने बताया कि मंजूरी इसी दिन शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी पक्ष को दे दी गई।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों की मदद हर संभव तरीके से जारी रखेगा। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया समूह गलत प्रचार कर रहे हैं और झूठी बातें फैला रहे हैं।

भारत का स्पष्ट रुख

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि पाकिस्तान का अनुरोध महज चार घंटे में मंजूर किया गयाजो न्यूनतम समय है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत ने पूरी तरह मानवता के आधार पर उठाया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों को अपने एयरस्पेस में उड़ान भरने पर रोक लगा रखी है। सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत के एयरस्पेस संबंधी फैसले तकनीकी, सुरक्षा और प्रक्रिया के आधार पर होते हैं, राजनीतिक नहीं। उन्होंने दोहराया कि सभी ओवरफ्लाइट या ट्रांजिट अनुरोध तय अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं के मुताबिक ही निपटाए जाते हैं।

मुद्रा लोन में फर्जीवाड़े का खुलासा

– यूको बैंक से 1.48 करोड़ की धोखाधड़ी में 17 लोगों पर केस

देहरादून। दून में कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के नाम पर मुद्रा लोन में लोगों के फर्जीवाड़े करने का खुलासा हुआ है। कारोबार के नाम पर 17 फर्म बनाकर 1.48 करोड़ रुपये का लोन लेकर मौके पर कारोबार नहीं किया गया। न ही बैंक को वापस लोन की रकम चुकाई। गढ़ी कैंट स्थित यूको बैंक शाखा में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर कैंट कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर कैंट केके लुंठी ने बताया कि बैंक की गढ़ी कैंट शाखा प्रबंधक अंकिता मिश्रा ने तहरीर दी। कहा कि बैंक ने 17 लोगों को कारोबार बढ़ाने या शुरू करने के लिए 1.48 करोड़ रुपये का लोन दिया। लोन देने के बाद आवेदकों ने किश्त जमा नहीं की। बाद में बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि लोन लेने वाले कई ग्राहकों ने कागजात फर्जी दिए। साथ ही, कई ग्राहकों ने जिस कारोबार के लिए लोन लिया था वह इकाई मौके पर मौजूद नहीं थी या बंद कर दी गई थी। आरोप लगाया कि इन लोगों ने साजिश रचकर बैंक को धोखा दिया और लोन की रकम को हड़प लिया।

जेल में बंद इमरान खान का दावा

आसिम मुनीर मानसिक रूप से बीमार, मुझे मरवा सकता है

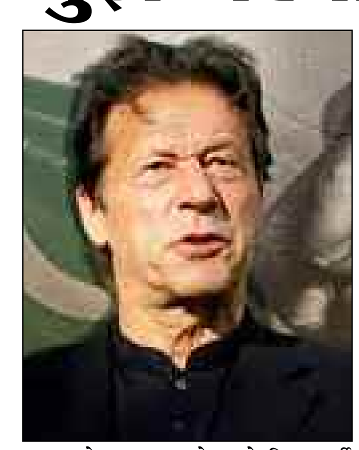

नई दिल्ली। अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। अपनी बहन डॉ उजमा खान से मुलाकात के बाद पीटीआई की ओर से जारी बयान में इमरान खान के हवाले से कहा गया कि सैन्य प्रतिष्ठान ने उनके खिलाफ हर संभव हथकंडा अपनाया है और अब उनके पास उनकी हत्या करवाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इमरान खान को पूरी तरह एकांत कारावास में रखा गया है, जहां न बिजली है, न धूप आती है, न बढ़िया खाना, न साफ पीने का पानी, न कोई मेडिकल सुविधा और न ही किसी कैदी को मिलने वाली सामान्य बुनियादी सुविधाएं। इस दौरान खान ने कहा कि उन्हें मौत की सजा पाए कैदियों जैसी स्थिति में रखा जा रहा है। पीटीआई के बयान के मुताबिक, पूर्व पीएम ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो मौत की सजा पाए कैदी को मिलती हैं। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को एकांत कारावास में रखकर बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने इन हालात को अमानवीय करार देते हुए कहा कि मुझे पिंजरे में बंद कर के प्रताड़ित किया जा रहा है और जानवरों से भी बदतर सलूक हो रहा है। मेरे सेल की बिजली पांच दिन तक बंद रही। दस दिन तक मुझे सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि मुनीर इतिहास के सबसे जालिम और मानसिक रूप से अस्थिर तानाशाह हैं। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच डॉ उजमा खान को रावलपिंडी की हाई–सिक्योरिटी अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। सीएनएन–न्यूज 18 के अनुसार यह मुलाकात 25 से 35 मिनट तक चली। उजमा खान के करीबियों के मुताबिक इमरान खान तंदुरुस्त, स्वस्थ और उत्साहित नजर आ रहे थे।

एसआईआर पर ममता बनर्जी की कड़ी नजर, निगरानी के लिए गठित की टीम

कोलकाता। बंगाल में जैसे–जैसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इसके प्रति विरोध तेज होता जा रहा है। ममता ने मंगलवार को रकफ पर निगरानी को 10 पर्यवेक्षकों की सरकारी टीम का गठन कर दिया है, जो जिलों में जाकर रकफ संबंधी कार्यों का मुआयना करेगी। बता दें कि आयोग ने बंगाल में रकफ के कामकाज पर निगरानी के लिए 13 पर्यवेक्षकों की विशेष टीम गठित की है।

ममता बनर्जी ने बनाई पर्यवेक्षकों की टीम

साथ ही मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कथित तौर पर रकफ के कारण जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनके परिवार को दो–दो लाख रुपये देने की भी घोषणा कर दी है। इसी तरह कथित तौर पर रकफ के कारण जो लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं, उन्हें एक–एक लाख रुपये दिए जाने की भी बात कही है। ममता का दावा है कि इनमें तीन बूथ स्तरीय अधिकारी भी शामिल हैं, जो काम के अत्यधिक दबाव के कारण बीमार पड़े हैं। कट सकते है 43 लाख लोगों के नाम : चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में अब तक रकफ में 43 लाख 30 हजार मतदाताओं के नाम कटने का हिसाब मिला है।

मृतकों के परिवारों को मुआवजा

यह गणना बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनमें से 21 लाख 45 हजार की मृत्यु हो चुकी है। पांच लाख 53 हजार मतदाताओं का पता नहीं चल सका है। 15 लाख 13 हजार स्थानांतरित हो चुके हैं। 98 हजार 600 फर्जी हैं।

आरोप है कि उनके नाम कई जगहों पर मतदाता सूची में हैं। आयोग 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित करेगा। इसके अलावा बंगाल के जिन 2208 बूथों पर 100 प्रतिशत गणना फार्म वापस आ गए हैं, आयोग ने उन्हें जांच के दायरे में रखा है।

भारी संख्या में सड़क किनारे मिले वोटर आइ कार्डनदिया जिले के नवद्वीप में मंगलवार को अस्पताल रोड के पास एक स्थान से बड़ी संख्या में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आइ कार्ड बरामद हुए। नवद्वीप पुलिस ने कार्ड जब्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी।

कांग्रेस ने 2003 व 2025 की विसवार वोटर लिस्ट मांगी

देहरादून। कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर आयोजित बैठक में 2003 व 2025 की विधानसभा वार वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की है।

सीडीओ व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों व पदाधिकारियों को आगामी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, महत्वपूर्ण तिथियों, मतदाता सूची के अद्यतन की प्रक्रिया तथा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए–2) की नियुक्ति एवं नामांकन से संबंधित आवश्यक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि प्रत्येक बूथ पर समयबद्ध रूप से बीएलए–2 की नियुक्ति सुनिश्चित करें। नियुक्त एजेंटों का विवरण निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।मतदाता सूची के सही एवं त्रुटिरहित पुनरीक्षण में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

ईसाई बनने पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा बनाए रखने को ह्यसंविधान के साथ धोखाधड़ीह्न के समान करार दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्मांतरण के बाद ईसाई बनने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले लाभ को उठाना जारी ना रखने पाये। उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा और अनुसूचित जाति के दर्जे के बीच अंतर को सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने साथ ही प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों के लिए ऐसे मामलों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए चार महीने की समय सीमा निर्धारित की। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने जितेंद्र साहनी नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश दिया। साहनी पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप है। साहनी ने इस आधार पर आरोप पत्र रद्द करने की मांग की थी कि उसने ईसा मसीह के उपदेशों का अपनी खुद की जमीन पर प्रचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति मांगी थी और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

एक भगवान पियक्कड़ों के, हिंदू देवताओं पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिगड़े बोल

नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने बयान को लेकर विवाद में फंसते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म में कई भगवान होने का मजाक उड़ाया है। इसको लेकर भाजपा और बीआरएस ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के सीएम एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में कई भगवान होने की बात का मजाक उड़ाया और यहां तक बोल गए कि हनुमान अविवाहित लोगों के भगवान हैं। रेड्डी ने कहाकि हिंदू कितने सारे भगवान में विश्वास करते हैं? करीब तीन करोड़? आखिर इतने सारे भगवान क्यों? उन्होंने आगे कहाकि इनके यहां तो अविवाहित लोगों का भी एक भगवान है। जिन लोगों ने दो बार विवाह किया है, उनके लिए एक और भगवान है। वहीं, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक अलग भगवान है। रेवंत रेड्डी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहाकि मुर्गियों की बलि चढ़ाने के लिए दूसरा भगवान और दाल–चावल के लिए दूसरा भगवान। हर ग्रुप का अपना एक अलग भगवान है।

विपक्ष ने की मांगी की मांग

रेवंत रेड्डी के बयान पर जबर्दस्त सियासी उबाल है। भाजपा और बीआरएस ने मुख्यमंत्री पर हिंदू आस्था और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रवीण ने कहाकि रेड्डी के बयान से प्रदेश के सभी हिंदू खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि कांग्रेस और रेवंत रेड्डी में बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। सभी बैठकों में वह लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की वजह से है। मुख्यमंत्री को अपना बयान वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।

आतंकी उमर के साथी आमिर की हिरासत 7 दिन और बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मामले के आरोपी आमिर रशीद अली की हिरासत अवधि को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यह फैसला तब आया जब आरोपी को उसकी 10 दिन की एनआईए हिरासत अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आमिर रशीद अली को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने अदालत से उसे पूछताछ के लिए हिरासत में देने की मांग की थी। अदालत ने पहले उसे 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था, ताकि एजेंसी उससे ब्लास्ट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और संभावित अन्य साजिशकर्ताओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके।

रुबैया सईद अपहरण केस में सीबीआई को झटका

35 साल बाद गिरफ्तार शांगलू को कोर्ट ने छोड़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मंगलवार को एक बड़ा झटका देते हुए एक विशेष अदालत ने 1989 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के सिलसिले में एक दिन पहले गिरफ्तार किये गए शफात अहमद शांगलू को रिहा कर दिया। शांगलू को विशेष टाडा अदालत में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने उसकी न्यायिक हिरासत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि वह रुबैया अपहरण मामले में वांछित है। आरोपी का प्रतिनिधित्व वकीलों की एक टीम ने किया, जिसमें अधिवक्ता अनिल रैना, सुहैल डार और योगेश बख्शी शामिल थे, जिन्होंने दलील दी कि शांगलू सीबीआई द्वारा कभी भी वांछित नहीं था और उन्होंने एजेंसी का आरोपपत्र भी पेश किया, जिसमें जांच अधिकारी (आईओ) का मानना था कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। रैना और डार ने सुनवाई के बाद पत्रकारों को बताया कि शांगलू को रिहा कर दिया गया है क्योंकि सीबीआई की सभी दलीलें 'असत्य' पाई गईं। राहत महसूस कर रहे शांगलू ने बाद में पत्रकारों को बताया कि वह एक व्यवसायी हैं और उसे 2016 में श्रीनगर में पासपोर्ट जारी किया गया था। इस दौरान उसने कहा कि मैं कभी किसी मामले में शामिल नहीं रहा। मैंने दिल्ली में लगभग 10 साल बिताए और अपने व्यवसाय के सिलसिले में कश्मीर और दिल्ली के बीच अक्सर यात्रा करता रहा। उसने कहा कि उसे उचित पुलिस सत्यापन के बाद 2016 में श्रीनगर में पासपोर्ट जारी किया गया था। यह पूछे जाने पर कि सीबीआई ने दावा किया है कि शांगलू एक फरार आरोपी है और उस पर 10 लाख रुपये का नकद इनाम है, बचाव पक्ष के वकीलों ने इसे 'मीडिया ट्रायल' करार दिया और कहा कि हम अदालती सुनवाई में विश्वास करते हैं।

सम्पादकीय

गौरा देवी एक मिसाल

पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड की गौरा देवी का पूरे देश में बेहद सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। गौरा देवी ने एक ऐसी मुहिम को विश्व पटल पर लाकर रखा था जिसने उत्तराखंड में कट रहे पेड़ों को एक नया जीवन दान दिया। गौरा देवी का "चिपको आंदोलन" पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन गया है और न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गौरा देवी का नाम पर्यावरण के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुका है। हालांकि आज भी गौरा देवी को राष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान और सम्मान शायद नहीं मिल पाया है जिसकी वह हकदार है और इसी बात को खास ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग उठाते हुए समस्त उत्तराखंड वासियों के दिल की बात रखी है। उन्होंने उच्च सदन में "चिपका डाल्थु पर न कंटण दख्वा, पहाड़ों की सम्पत्ति अब न लूटण दख्वा।" सुनाकर उनके पर्यावरण संरक्षण में दिए अतुलनीय योगदान को याद किया। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी की 53 वर्ष पूर्व एक सीधी सादी पहाड़ों में रहने वाली सामान्य सी गुमनाम महिला पर्यावरण को लेकर झूठे दिखावों से दूर पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरेंगी जिसकी गूंज कई दशक तक सुनाई देगी। गौरा देवी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशीमठ विकास खण्ड के रेणी गांव की ग्रामीण महिला थी , जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति के द्वारा वृक्षों के आलंगन से जुड़ा आंदोलन था। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1970 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ जब पेड़ो को काटने वाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूरों को भेजा तब गोरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ो से चिपक गई यह कह कर कि पेड़ो को काटने से पहले उन्हें काटा जाय। इस आंदोलन की गूंज को भारत सहित संपूर्ण दुनिया ने सुना। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण बड़ा मुद्दा बना दिया और यह आंदोलन भारत के हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान तथा बिहार राज्यों तक फैल गया। इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि तत्कालीन भारत सरकार ने 15वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी के संघर्षों की कहानी है, जंगल प्रकृति के लिए कितने मूल्यवान है उस आंदोलन के गीत में निहित है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की यह मांग उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं के अनुरूप तो है ही साथ ही यदि केंद्र सरकार इस पर सहमत होती है तो पर्यावरण की दिशा में यह उत्तराखंड के लिए बेहद गौरव की बात भी होगी।

दिन ब दिन बढ़ रही मजदूरों की मुश्किलें

अजीत द्विवेदी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक स्थायी दावा होता है कि वह जो भी काम कर रही है वह सबसे बड़ा काम है या ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। तभी छह साल पहले 2019 में भारतीय संसद से पास चार श्रम कानूनों को लागू करते हुए ऐसा ही दावा किया गया है। हैरानी की बात है कि अनेक मीडिया समूह भी अपने संपादकीय में इन कानूनों को इसी रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में किसी भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ध्यान रहे अब तक 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की ओर से लागू किए गए उदारीकरण के फैसले को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता रहा है। अब उसकी जगह श्रम कानूनों को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह सबसे बड़ा कथित आर्थिक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को वैसे ही बदल पाएगा, जैसे 1991 के आर्थिक सुधारों ने बदला था? और क्या इससे श्रमिकों की हालत में कोई गुणात्मक परिवर्तन आएगा? इसकी संभावना कम है।

बुनियादी रूप से ये चारों कानून कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एकमात्र बड़ी खासियत दिखाई दे रही है वह ये है कि पहले से मौजूद 29 केंद्रीय कानूनों को इन चार कानूनों में समेटा गया है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले इन 29 कानूनों की वजह से उद्योग व कारोबारी समूहों को इनके अनुपालन में समस्या आती थी तो दूसरी ओर श्रमिकों के लिए जरूरी लाभ उपलब्ध कराना मुश्किल होता था। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इससे मजदूरों को कैसे फायदा होगा? इस सवाल पर विचार से पहले चारों कानूनों के बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। ये चार कानून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता हैं।

पहला कानून यानी वेतन संहिता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मजदूरों को एक निश्चित वेतन मिले, वेतन समय पर मिले और वह उचित हो। पहले वेतन, भत्ता, पेंशन, बोनस आदि के लिए अलग अलग कानून थे, जिससे परेशानी होती थी। इसमें एक खास बात यह है कि महिलाओं को पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। हालांकि उचित और समय पर वेतन मिलना कैसे सुनिश्चित होगा यह कानून लागू होने के बाद पता चलेगा। दूसरा कानून औद्योगिक संबंध संहिता हैं, जिसके तहत कर्मचारी और कंपनी के संबंधों की व्याख्या की गई है और साथ ही दोनों के बीच विवाद के त्वरित निपटान की व्यवस्था भी बनाई गई है। इसमें हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के नियम भी शामिल किए गए हैं और सबसे ज्यादा विरोध इसी नियम का हो रहा है।

तीसरा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता का है, जिसमें असंगठित मजदूरों, ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले लोग, जिन्हें गिग वर्कर्स कहा जा रहा है उनके लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में कहा गया है कि कंपनियां इनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाएंगी। इस कानून के जरिए स्वास्थ्य, बीमा और मातृत्व सुविधा जैसे लाभों को हासिल करना आसान बनाया जाएगा। चौथा और अंतिम कानून व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता है, जिसमें कर्मचारियों, मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है साथ ही कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों को दूर करके उसे बेहतर बनाने के उपाय भी किए गए हैं। पहले से मौजूद 13 कानूनों मिला कर इसे बनाया गया है। इसमें महिलाओं के रात में काम करने का प्रावधान भी किया गया है।

दावा किया जा रहा है कि यह अद्भुत संतुलन वाला कानून है, जिससे मजदूरों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा तो उद्योग समूहों को भी लाभ होगा। सवाल है कि जब दोनों के लिए फायदे वाला कानून है तो इसे लागू करने में सरकार को छह साल क्यों लग गए? दूसरा सवाल

यह है कि अगर ये कानून मजदूरों के हित में हैं तो देश के ज्यादातर बड़े मजदूर संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में संसद में पास करने से लेकर इनके नियम बना कर इन्हें लागू करने तक जब भी इन कानूनों की बात होती है तो दावा किया जाता है कि इनसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर व उचित वेतन मिलेगा तो दूसरी ओर कंपनियों को एक ऐसा सरल ढांचा मिलेगा, जिसके अनुपालन में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह सिर्फ सदिच्छा है। वास्तव में इसका कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा।

परंतु उससे पहले इस कानून के कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनको मजदूर फ्रेंडली कतई नहीं माना जा सकता है। उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों को नियमों में बांधने, उनके विरोध करने की क्षमता को कम करने और उनकी नौकरी को असुरक्षित बनाने के प्रावधान इन कानूनों में निहित हैं। मिसाल के तौर पर औद्योगिक संबंध संहिता में प्रावधान किया गया है कि तीन सौ तक मजदूर और कर्मचारी वाला उद्योग सरकार की अनुमति के बगैर छंटनी कर सकता है। पहले एक सौ मजदूरों तक की कंपनियों को यह छूट मिली थी। यह दायरा बढ़ाने का मतलब है कि देश की ज्यादातर कंपनियां और उद्योग अपने यहां पहले से ज्यादा आसानी से छंटनी कर पाएंगे। इसमें लगभग पूरा एमएसएमई सेक्टर आ जाता है। ध्यान रहे भारत में ज्यादातर कंपनियां इतने की मजदूरों या कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने ज्यादातर मजदूरों को कंपनियों की मर्जी के हवाले कर दिया है।

इतना ही नहीं मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया है। नए कानून में प्रावधान है कि हड़ताल से 60 दिन यानी दो महीने पहले नोटिस देना होगा। सोचें, अगर कर्मचारी या मजदूर अपनी किसी समस्या के लिए तत्काल विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर पाएंगे तो उनकी समस्या को निराकरण कैसे होगा? आवश्यक सेवाओं पर लागू होने वाले कानून को हर तरह के मजदूरों और कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है। इससे उनके विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यूनियन की मान्यता पाने के लिए कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या के 10 फीसदी या एक सौ मजदूरों का, जो भी ज्यादा हो, उसमें शामिल होना जरूरी है। इससे छोटी

बुनियादी रूप से ये चारों कानून कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एकमात्र बड़ी खासियत दिखाई दे रही है वह ये है कि पहले से मौजूद 29 केंद्रीय कानूनों को इन चार कानूनों में समेटा गया है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले इन 29 कानूनों की वजह से उद्योग व कारोबारी समूहों को इनके अनुपालन में समस्या आती थी तो दूसरी ओर श्रमिकों के लिए जरूरी लाभ उपलब्ध कराना मुश्किल होता था। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इससे मजदूरों को कैसे फायदा होगा? इस सवाल पर विचार से पहले चारों कानूनों के बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। ये चार कानून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता हैं। पहला कानून यानी वेतन संहिता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मजदूरों को एक निश्चित वेतन मिले, वेतन समय पर मिले और वह उचित हो। पहले वेतन, भत्ता, पेंशन, बोनस आदि के लिए अलग अलग कानून थे, जिससे परेशानी होती थी।

यूनियन के समाप्त होने का खतरा है।

सामाजिक सुरक्षा वाले तीसरे कानून में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड की बात कही गई है। लेकिन यह फंड कैसे बनेगा? कंपनियां कितना योगदान करेंगी और मजदूरों को उसका लाभ कैसे मिलेगा इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा वाले चौथे कानून में रोज के काम के घंटे का विस्तार 12 घंटे तक कर दिया गया है। कंपनियां आठ से 12 घंटे काम करा सकेंगी। हालांकि एक हफ्ते में काम की अधिकतम सीमा 48 घंटे निर्धारित है लेकिन सबको पता है कि इस सीमा का पालन कहीं नहीं होता है। नया कानून लागू होने के बाद कंपनियां लंबे कार्य दिवस लागू कर सकती हैं, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा।

असल में नए श्रम कानून जैसा कि हमेशा होता है उद्योग समूहों और निवेशकों के हितों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना और उद्योग समूहों का विस्तार करना है। सभी सरकारें मानती रही हैं कि उद्योगों का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और संपन्नता आएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कानून शोषण और गैर बराबरी को बढ़ाता है। ये कानून भी अपवाद नहीं हैं। इनमें भी फिक्स्ड टर्म नौकरी पर जोर दिया गया है, जिसका मतलब है कि स्थायी नौकरियां कम होंगी और ठेके पर काम ज्यादा उपलब्ध होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी नहीं कम होगी। इसी तरह कंपनियां नियमों का कैसे अनुपालन करती हैं उसकी जांच और निगरानी की व्यवस्था कमजोर कर दी गई है। कई मामलों में तो कंपनियों को स्व प्रमाणन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई है। श्रम कानूनों को अनुपालन में आसान और लचीला बनाने वाले तर्क अपनी जगह हैं। लेकिन काम के घंटे बढ़ाने, छंटनी के नियम आसान करने, यूनियन बना कर हड़ताल करने के नियम सख्त करने और निगरानी की व्यवस्था को कमजोर करने से अंततः मजदूरों की मुश्किलें बढ़ेंगी और उद्योग समूहों को उनके शोषण का अधिकार मिलेगा।

नीतीश का दांव सटीक पड़ा

पिछले वित्त वर्ष में जिस राज्य में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के नौ फीसदी से ज्यादा रहा हो और जहां बजट का 64 प्रतिशत हिस्सा फिक्स्ड मदों में जाता हो, वहां ये सवाल अहम है कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा? बिहार में चुनाव से ठीक पहले करोड़ों मतदाताओं को नकदी ट्रांसफर करने (या करने का वादा करने) का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दांव सटीक पड़ा। बेशक, एनडीए के पास बड़ा जातीय समीकरण है, जिससे दो दशक से उसे मजबूत मत आधार मिला हुआ है। फिर भी "कल्याणकारी कदमों" से 'अतिरिक्त वोटड्ढ जुटाने की चुनौती उसके सामने बनी रहती है। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में उसने बेतुके- जैसे दिखने वाले वादे भी

किए। एक आकलन के मुताबिक इससे राज्य सरकार के बजट पर 28,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रेकरिंग (यानी हर साल पड़ने वाला) है। पिछले वित्त वर्ष में जिस राज्य में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के नौ फीसदी से ज्यादा रहा हो और जहां बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा फिक्स्ड मदों में जाता हो, वहां ये सवाल अहम बना रहेगा कि ये अतिरिक्त धन कहां से आएगा? चुनाव से पहले वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन में बढ़ोतरी लागू कर और दो लाख रुपये देने की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये का अग्रिम भुगतान तकरीबन डेढ़ करोड़ महिलाओं को करके नीतीश कुमार ने अपने वादों की साख कायम की। इसका असर मतदान में दिखा। मगर अब सवाल बाकी 1,90,000 रुपये देने, पीएम किसान योजना के तहत 3,000 रुपये का टॉप ऑप भुगतान करने, मछुआरा समुदाय को नौ हजार रुपये तक देने, अनुसूचित जाति के छात्रों को हर महीने दो हजार रुपये देने, अति पिछड़ा समुदाय के कुछ हिस्सों को 10 लाख रुपये की सहायता देने, और 1000 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का है। क्या इनके लिए धन शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अभी ही बेहद कम बजट में कटौती कर जुटाया जाएगा? या बुनियादी ढांचे में निवेश घटाया जाएगा? या ऋण का बोझ बढ़ा कर अगली पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगाया जाएगा? यह निर्विवाद है कि बिना पूंजीगत निवेश में भारी कटौती या ऋण लिए उपरोक्त वादों को निभाना संभव नहीं है। लाभान्वित मतदाता इसके परिणामों की चिंता करें, यह अपेक्षा निराधार है- खासकर तब जबकि रहबर ही सियासी स्वार्थ में हर तार्किक चिंता की बलि चढ़ा चुके हों!

जहरीली हुई हवा पर सरकार बेफिक्री

संभवतः सरकार की निगाह में उससे असहमत या उसकी नाकामियों पर बात करने वाली हर आवाज अवैध है, इसलिए प्रदूषण पर बेफिक्री के खिलाफ इंडिया गेट पर जुटे महिलाओं और बुजुर्गों तक को पुलिस जबरन अपनी बसों में ले गई। दिल्ली में जहरीली हुई हवा पर सरकारी बेफिक्री के खिलाफ नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास इक्ा हुए नागरिकों से पुलिस ने वैसा ही सलूक किया, जैसा इस दौर में किसी भी विरोध प्रदर्शन के साथ किया जाता है। संभवतः भारत सरकार की निगाह में उससे असहमत या उसकी नाकामियों पर बात करने वाली हर आवाज अवैध है, इसलिए इंडिया गेट पर जुटे महिलाओं और बुजुर्गों तक को पुलिस जबरन अपनी बसों में ले गई। दूर बवाना ले जाकर उन्हें छोड़ा गया। आयोजकों से यह लिखित वादा भी लिया गया कि समन पर वे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होंगे। विरोध जताने आए नागरिकों की कोई राजनीतिक मांग नहीं थी। वे सिर्फ यह पूछ रहे थे कि उन्हें और उनके बच्चों को साफ हवा में सांस लेने का हक भी नहीं है? दिल्ली में आज यह आम धारणा है कि सरकार ने इस वर्ष इस सीजन में प्रदूषण का असली स्तर छिपाने की कोशिश की है। इस सूचना पर सुप्रीम कोर्ट भी जवाब- तलब कर चुका है कि वायु गुणवत्ता की जांच करने वाले 37 में से 28 केंद्र दिवाली के दिन बंद थे। फिर इल्जाम हैं कि जहां ये प्रदूषण की माप करने वाली मशीनें लगी हैं, वहां दिल्ली सरकार ने जानबूझ कर जल छिड़काव कराया, ताकि प्रदूषण की मात्रा कम दर्ज हो। इन बातों ने नागरिकों में व्यग्रता पैदा की है। उनमें इसको लेकर भी आक्रोश है कि हवा के लगातार जहरीली बनी होने के बावजूद दिल्ली या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई हरकत नहीं दिखी है। अरविंद केजरीवाल सरकार के समय कम-से-कम ऑड-इवन जैसी योजनाओं की चर्चा होती थी। चूंकि तब भाजपा दिल्ली में विपक्ष में थी, तो उसके प्रभाव से मेनस्ट्रीम मीडिया में भी यह मुद्दा गरमाया रहता था।

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंड 2: थांडवम का दमदार टीज़र रिलीज

डायरेक्टर बोयापेटी श्रीनु की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर अखंडा 2: थांडवम के मेकर्स ने, जिसमें एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण लीड रोल में हैं, अब फिल्म का एक्शन से भरपूर टीज़र रिलीज़ कर दिया है, जिससे फैंस और फिल्म के दीवाने बहुत खुश हैं। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर टीज़र के तमिल और तेलुगु वर्शन के लिंक शेयर किए। इसमें लिखा, हर फ्रेम, हर शॉट में द डिवाइन फ्यूरी दिख रहा है। अखंडा 2 का बड़ा थांडवम टीज़र अब आ गया है। 5 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में। नए रिलीज़ हुए टीज़र में दिखाया गया है कि देश के दुश्मन भारत की जड़ों पर हमला करने की साज़िश कर रहे हैं। फिर हम बालकृष्ण को देखते हैं, जो साधु के वेश में हैं, और अपने खास अनोखे अंदाज़ में कहते हैं, जहाँ बुराई होती है, वहीं भगवान भी होता है!

बहादुर बनो। टीज़र वही दिखाता है जो ट्रेलर में दिखाया गया था -- कि बालकृष्ण के अंदर एक दिव्य शक्ति काम करती है और वह भारत के दुश्मनों की मदद करने वाले ताकतवर काले जादू करने वालों का सामना करते हैं। टीज़र, जिसमें बालकृष्ण की बेटी उन्हें पुकारती है, फिल्म के रोमांचक एक्शन सीक्वेंस की एक झलक देता है।

अभिनय की दुनिया एक अलग जिंदगी जीने की आजादी देती है: निमरत कौर

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जब भी कोई नया सीजन रिलीज होता है, तो दर्शक सबसे पहले यह देखना चाहते हैं कि उनके पसंदीदा किरदारों के साथ क्या नया हुआ है और कौन से नए किरदार कहानी में जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में रिलीज हुई द फैमिली मैन सीजन 3 ने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा है। तीसरे सीजन में एक नया किरदार मीरा दर्शकों के लिए खासा दिलचस्प साबित हुआ। इस किरदार को अभिनेत्री निमरत कौर ने निभाया। इस किरदार को लेकर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। निमरत कौर ने कहा, मीरा का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत शानदार अनुभव रहा। इस रोल ने मुझे महिला सशक्तीकरण की भावना महसूस करने का मौका दिया। यह किरदार न केवल कहानी में अहम है, बल्कि यह दर्शाता है कि एक महिला अपने तरीके से किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, चाहे वह पुरुषों की दुनिया में काम कर रही हो या फिर नेतृत्व की भूमिका में हो। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह अनुभव इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसके सभी लेखक पुरुष ही थे, जिन्होंने महिला सशक्तीकरण के अलग पहलुओं को दिखाया।

बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाज बरपाएंगे कहर

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। ये मैदान एक तरह से नया है और ज्यादा मैचों की मेजबानी का अनुभव इस मैदान को नहीं है। ऐसे में सभी की नजरें स्टेडियम की पिच पर होंगी। पिच क्रिकेट में काफी अहम रोल अदा करती है और इसलिए दोनों टीमें सबसे पहले पिच पर नजरें जमाती है।

पिच के हिसाब से ही टीमें अपनी प्लेइंग-11 चुनती है। ये मैदान नया है और इसलिए किसी को ज्यादा पता नहीं है कि पिच का मिजाजा कैसा है। फैंस तो चाहेंगे कि यहां रनों का बारिश हो और रांची जैसा मुकाबला देखने को मिले।

ऐसी है पिच

जहां तक पिच की बात है तो ये तेज गेंदबाजों के लिए बेहतर मानी जाती है और इसलिए बल्लेबाजों को परीक्षा देनी पड़ सकती है। तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिलेगी और ऐसे में भारत को सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं। इस मैच से पहले यहां साल 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ था। वो भी वनडे मैच था जिसमें कीवी टीम महज 108 रनों पर ढेर हो गई थी। नई गेंद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने कहर ढा दिया था।

हर्षित राणा ने रांची में शानदार गेंदबाजी की थी। उनको इस पिच से मदद मिल सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा भी इस पिच पर कमाल कर सकते हैं। दोनों ही गेंदबाजों के पास अच्छी लंबाई है जिसके चलते दोनों को उछाल मिलता है। अगर पिच से सीम और स्विंग मिलती है तो फिर अर्शदीप भी कहर बरपाने का दम रखते हैं।

बल्लेबाजों की मुसीबत

दोनों ही टीमों के पास अच्छे गेंदबाज हैं और इसलिए बल्लेबाजों की भूमिका अहम हो जाती है। जिस टीम के बल्लेबाज पिच से मदद मिलने वाली गेंदबाजी का सामना अच्छे से करते हैं वो टीम जीत हासिल कर सकती है। भारत के पास रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल का अनुभव है जो उसे बढ़त दिलाता है।

बॉक्स ऑफिस पर चला तेरे इश्क में का जादू, दूसरे दिन हुई दमदार कमाई

इंटेंस लव स्टोरीज एक बार फिर थिएटर्स में सेंटर स्टेज पर आ रही हैं, और तेरे इश्क में को मिला रिस्पॉन्स इसका सबूत है. रोमांटिक जॉनर में आई सुस्ती के बाद, इस फिल्म ने दर्शकों को बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में वापस ला खड़ी कर दी है. फिल्म ने जहां पहले दिन डबल डिजिट में कमाई करने में सफल रही, वही दूसरे दिन इसने उछाल मारी और पहले दिन की अपेक्षा ज्यादा कमाई की. आनंद एल. राय के डायरेक्शन में बनी यह दिल को छू लेने वाली म्यूजिकल लव स्टोरी 28 नवंबर सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिले. रांझणा जैसी ही तेरे इश्क में ने दर्शकों को इम्प्रेस किया है. बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग के बाद, फिल्म ओपनिंग वीकेंड में खूब चर्चा में है, और इसने विजय राज और फातिमा सना शेख की गुस्ताख इश्क को भी पीछे छोड़ दिया, जो मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोड्यूसर के तौर पर पहला प्रोजेक्ट था, जो कल ही थिएटर में रिलीज हुई थी. धनुष की मैड लवर बॉय कैरेक्टर शंकर और कृति सेनन की मुक्ति के रूप में, तेरे इश्क में ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया और थिएटर में अपनी यात्रा को शानदार तरीके से शुरू किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने डबल-डिजिट में ओपनिंग की और पहले दिन 16 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें से 15.25 करोड़ हिंदी बेल्ट से आए. बता दें कि धनुष-कृति सेननन स्टारर यह फिल्म हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. फिल्म के को-प्रोड्यूसर टी-सीरीज के पोस्ट के मुताबिक, तेरे इश्क में ने पहले दिन 15.05 करोड़ (हिंदी नेट) कमाए.

मैदान पर लौटते ही गरजा हार्दिक का बल्ला, वैभव सूर्यवंशी का शतक गया बेकार

हैदराबादः दो महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के विरुद्ध नाबाद 77 रनों की पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी-20 सीरीज के लिए दावा ठोक दिया। उनकी इस पारी के दम पर बड़ौदा ने ग्रुप सी मुकाबले में पंजाब को सात विकेट से हराया। हार्दिक ने 42 गेंद में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से यह पारी खेली। पंजाब ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 222 रन बनाए थे, जिसमें पिछले मैच में 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 50 रन बनाए। लेकिन उनकी यह पारी बेकार गई। हार्दिक की पारी के दम पर बड़ौदा ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 224 रन बनाए। सितंबर में दुबई में एशिया कप सुपर फोर्स में श्रीलंका के विरुद्ध खेलने के बाद हार्दिक का पहला प्रतिस्पर्धी मैच था। उन्होंने चार ओवर गेंदबाजी करके 52 रन दिए और एक विकेट भी लिया। हार्दिक को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खेलने की अनुमति मिली थी। मैदान पर हार्दिक की वापसी पर प्रशंसक उनके साथ सेल्फी लेते दिखे।

दिल्ली क्रिकेट का बुरा हाल

अहमदाबाद में दिल्ली का मौजूदा घरेलू सत्र में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। ग्रुप डी के मैच में आईपीएल खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद उसे त्रिपुरा की कमजोर मानी जाने वाली टीम के विरुद्ध पहली बार 12 रन से हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा घरेलू सत्र में रणजी ट्रॉफी में भी दिल्ली को जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध पहली बार शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली और सचिव अशोक शर्मा को टीम चयन, सहयोगी स्टाफ के चुनाव और सरनदीप सिंह की नियुक्ति को लेकर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। टीम चयन की लगभग हर बैठक में चयनकर्ताओं के साथ सचिव अशोक शर्मा और संयुक्त सचिव अमित ग्रोवर बैठते हैं। किसी भी राज्य में चयनकर्ताओं के साथ उस राज्य संघ के दो-दो पदाधिकारी नहीं बैठते। आरोप लग रहे हैं कि चयनकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए चयनसमिति में इन दोनों को बैठाया जाता है।

एक नजर

कोट ब्लॉक के छः आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विकासखंड कोट के आंगनबाड़ी केंद्र देवार से घर लौट रहे मासूम पर गुलदार के हमले के बाद क्षेत्र में दशहत का माहौल है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्षेत्र के 6 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन दिन तक अवकाश घोषित कर दिया है। तीन दिन बाद समीक्षा करने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर निर्णय लिया जायेगा।

डीपीओ पौड़ी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र देवार की आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुषमा ने गुलदार के हमले से मासूम को बचाने में सराहनीय भूमिका निभाई। विभाग उनकी प्रशंसा करता है। बताया कि घटना के बाद क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र देवार के साथ-साथ वड्डा, चमना, कांडा, नवन व बुरांसी में तीन दिन का अवकाश घोषित किया है। तीन दिन बाद नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन व वन विभाग के साथ समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों खोलने या अवकाश को बढ़ाएं जाने पर निर्णय लिया जाएगा।

कांग्रेसी आज करेगें तहसील का घेराव

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विधानसभा चौबट्टाखाल में गुलदार, भालुओं व जंगली जानवरों से निजात दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस बुधवार को तहसील में घेराव करेगी। कांग्रेसियों का कहना है कि गुलदार की दहशत से कारण कई स्कूलों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोखड़ा अध्यक्ष बिजेंद्र दर्शन रावत ने क्षेत्र के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों से घेराव में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की है।

खेल प्रतियोगिताओं में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : राजकीय महाविद्यालय सतपुली, खैरासैंण में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र-छात्राओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. संजय कुमार ने किया। इस दौरान 200, 400 मीटर दौड़ के साथ ही गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, म्यूजिकल चेयर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इस मौके पर प्राचार्य प्रो. संजय कुमार, महाविद्यालय के कीड़ा प्रभारी डा. कुमार विमल लखटकिया, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो. राकेश इस्टवाल, डा. संजीव कुमार, डा. हिमानी बिष्ट, डा. अवधेश कुमार उपाध्याय मौजूद रहे।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हिमाचल की तर्ज पर मानदेय देने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए अपेक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाने, सदस्यों को हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर 9 हजार रुपये का मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर क्षेत्र पंचायत संगठन कीर्तिनगर ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी से वार्ता की। क्षेपं सदस्यों ने ज्ञापन प्रेषित करते हुए जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की मांग की। उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को सौंपे ज्ञापन में कनिष्ठ प्रमुख प्रियंका जायड़ा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रानीहाट मनोज कुमार जोशी ने कहा कि सरकार क्षेत्र पंचायतों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है। कहा कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (1992) में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को वरीयता और संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, जिसमें क्षेत्र पंचायतों को एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया था, जबकि उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट, 2016 की धारा 192 में भी मानदेय का प्राविधान विहित है। इसके बावजूद भी क्षेत्र पंचायतों को व्यवस्था से पूर्णतः नजरअंदाज किया गया है।

कहा कि पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में क्षेत्र पंचायतों को आवश्यक वरीयता तथा सोलह दिन की मासिक बैठकें दी गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं की गई है,जिससे क्षेत्र पंचायत सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने क्षेत्र पंचायतों के लिए एक निश्चित वित्तीय निधि आवंटित किए जाने, क्षेत्र पंचायतों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर 9 हजार रूपये का मानदेह प्रदान करने, विकास कार्य के लिए वार्षिक निधि न्यूनतम 10 लाख रूपये आवंटित किए जाने की मांग की है। सदस्यों ने जल्द मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य मंजाकोट अंजलि, क्षेत्र पंचायत सदस्य सिरवाड़ी जेएस रावत आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

जुर्माने के चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद भी जनता को नहीं निगम का डर

कोटद्वार में सड़क किनारे फैला कूड़ा

शहर के मुख्य चौराहों के साथ ही गली-मोहल्लों में लगे गंदगी के ढेर

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : शहर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। बाजूवद कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हालत यह है कि नगर निगम की चेतावनी के बाद भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े का ढेर डाल रहे हैं। जबकि, नगर निगम ने सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने वालों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं। साथ ही सड़क किनारे कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन चेतावनी बोर्ड के आसपास ही सबसे अधिक कूड़े का ढेर लगा रहता है।

आमजन को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम की ओर से समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। कुछ माह पूर्व ही नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया था। इसके तहत घर-घर जाकर लोगों को घरों से निकलने वाली गंदगी को निगम के कूड़े वाहनों में डालने की अपील की गई। लेकिन, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर की स्वच्छता पर पलीता लगा रहे हैं। घर-घर कूड़ा गाड़ी पहुंचने के बावजूद खाली प्लाट व सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर डाले जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने व जुर्माने की चेतावनी के बाद भी यह लोग अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। हालांकि पूर्व में नगर निगम सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डालने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी कर चुका है। सबसे बुरी स्थिति ऊर्जा निगम को जाने वाले मार्ग, देवी रोड, मानपुर रोड, गाड़ीघाट क्षेत्र में बनी रहती है।

चालीस फीसद घरों से आ रहा कूड़ा

कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के चालीस वार्डों में करीब 45 हजार मकान है। जहां करीब डेढ़ लाख की आबादी रहती है। घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए नगर निगम की ओर से प्रत्येक वार्ड में कूड़ा वाहनों का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों टन कूड़ा वार्डों से एकत्रित कर उसे गाड़ीघाट ट्रैंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। जहां कबाड़ अलग कर अवशेष की खाद बनाई जाती है। नगर निगम डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के एवज में घरों से महीने का तीस रुपये चार्ज वसूलता है। लेकिन, शहर के मात्र चालीस फीसद घरों से ही निगम के वाहनों में कूड़ा डाला जा रहा है। आज भी कई लोग खाली प्लाट व सड़क पर कूड़ा डाल रहे हैं। जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है।

गांव में घूम रहा गुलदार, दहशत में लोग

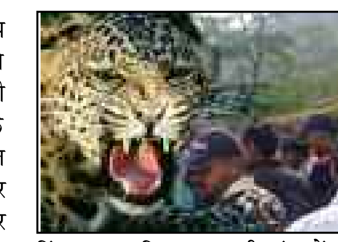

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की धमक थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर पोखड़ा के घंडियाल गांव में गुलदार की दहशत फैल गई है। क्षेत्र में लगातार दो-तीन गुलदार नजर आ रहे हैं। रविवार शाम एक गुलदार गांव में ही पहुंच गया, जिसे ग्रामीणों ने शोर मचाकर गांव से दूर किया। बताते चलें कि बीती 15 नवंबर को गुलदार ने घंडियाल निवासी प्रभा देवी पर उस समय हमला किया जब वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ खेत में घास लेने के लिए गई हुई थी। प्रभा देवी ने दरांती से गुलदार पर वार कर खुद को उसके चंगुल से बचाया। ग्रामीणों ने घायल प्रभा देवी को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया। इस घटना के बाद वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगा दिया। साथ ही गांव में वन कर्मियों की भी तैनाती की गई। 22 नवंबर की सुबह करीब छः बजे पिंजरे में एक गुलदार कैद हुआ। जिसे वन महकमे की टीम अपने साथ ले गई। उधर, इस गुलदार के कैद होने के बाद भी क्षेत्र में लगातार गुलदार नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विनोद बिंजोला ने बताया कि रविवार शाम एक गुलदार गांव में पहुंच गया, जिससे गांव में दहशत हो गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर गुलदार को जंगल की ओर खदेड़ा।

गुलदार के हमले में मासूम घायल, दहशत में ग्रामीण

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंज में गुलदार का आतंक थमने का नाम ले रहा है। मंगलवार को दिनदहाड़े गुलदार ने कोट ब्लाक के देवार गांव में आंगनबाड़ी से घर जा रहे चार साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे के सिर पर घाव बने हैं। घायल बच्चे का जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार किया गया। घटना से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने उपवन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश जारी करने की मांग की है। देवार के ग्राम प्रधान गौरव कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेम सिंह ने बताया कि मंगलवार की दोपहर को करीब साढ़े 12 बजे चार साल का अनमोल आंगनबाड़ी से छुट्टी के बाद अपनी मां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान छुंयाधार के पास घात लगाए गुलदार ने अनमोल पर हमला कर दिया। बताया कि अनमोल की मां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीणों के शोर करने पर गुलदार भाग गया। घायल अनमोल को जिला अस्पताल में लाया गया। अनमोल के सिर पर हल्के घाव आए हैं। अस्पताल में उपचार के बाद अनमोल को छुट्टी दे दी गई है। ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ग्राम प्रधान गौरव रावत ने बताया कि उपवन संरक्षक को एक शिष्टमंडल द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में गुलदार को मारने के आदेश जारी करने की मांग की है, यदि समय रहते वन विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं नहीं की जाती है तो ग्रामीणों द्वारा जल्द वन विभाग का घेराव कर जनांदोलन किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। उपवन संरक्षक आइशा बिष्ट ने बताया है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और पिंजरा लगाने की अनुमति मांगी गई है। विभाग द्वारा इस घटनाक्रम का संज्ञान में लिया गया है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान गौरव रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवार प्रेम सिंह, जिला पंचायत सदस्य आराधना देवी, गौरव रावत अध्यक्ष कोआपरेटिव समिति वजली, विवेक रावत, गौरव सागर, नितिन रावत आदि मौजूद रहे।

सिद्धबली अनुष्ठान के दौरान बंद रखी जाएं मांस की दुकानें

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : हिंदू जागरण मंच ने श्री सिद्धबली वार्षिक अनुष्ठान के दौरान मांस की दुकानों को बंद करवाने की मांग की है। कहा कि श्री सिद्धबली बाबा से सैकड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में मंदिर जाने व आने वालों की आस्था में विघ्न न हो, इसके लिए गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

इस संबंध में सदस्यों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। कहा कि पांच दिसंबर से तीन दिवसीय श्री सिद्धबली अनुष्ठान का आयोजन होना है। इस अनुष्ठान में शहर के साथ ही अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में बाबा के भक्त शामिल होंगे। ऐसे में शहर में भक्ति का माहौल बना रहे इसके लिए मांस की दुकानों को तीन दिन के लिए बंद रखा जाना चाहिए। कहा कि महोत्सव के पहले दिन शहर में झांकी भी निकलनी है, इसलिए प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर जतिन रावत, शिवांश, बब्लू नेगी, सौरभ गोदियाल, प्रीतम सिंह आदि मौजूद रहे।

जीतू बगड़वाल ने नाटक-नृत्य में प्राप्त किया प्रथम स्थान

आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देती छात्राएं

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : मालिनी वैली कॉलेज ऑफ एजूकेशन में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान नाटक-नृत्य प्रतियोगिता में जीतू बगड़वाल ने प्रथम स्थान प्रप्त किया।

कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। जिसमें बीएड के छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी तत्पश्चात नेहा ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। अनुराधा, प्रियंका व अनु ने ह्नशिव कैलाशो के वासीह्न गीत गायक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयुष, नरेश और सूरज ने विभिन्न गीत प्रस्तुत किए। संस्कृत भारती, कोटद्वार के डॉ. कुलदीप मैंदोला ने मालिनी श्रेत्र की दशा पर अपने विचार रखे।

डॉ. राकेश कंडवाल जी की सार्थक योगशाला के नन्हे योगियों ने योग का सुंदर प्रदर्शन किया। बीएड प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं ने मांगल गीत से सबका मन मोह लिया। साथ ही ह्नजीतू बगड़वालह्न नामक नाटक का मंचन किया गया। अंत में एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र विकास ने किया। महाविद्यालय के अध्यक्ष योगम्बर सिंह ने माल्यार्पण द्वारा अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसके जज डा. मंजू कापरवाण, राकेश कंडवाल व डा. रमाकांत कुकरेती थे। नाटक जीतू बगड़वाल प्रथम, एकल नृत्य नेहा द्वितीय व मंगल गीत तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर निदेशक स्वेता रावत, प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रभा जोशी, प्रकाश चंद्र, डा. रुनामी शर्मा, सुभाष ढौंडियाल, सौरव नेगी, डॉ. कुलदीप मैंदोला, विकास देवरानी आदि मौजूद रहे।

शिविर में 1226 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य की जांच

कोटद्वार के श्री गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में आयोजित शिविर के दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए पंजीकरण करवाते लोग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 1226 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस दौरान लोगों के खून सहित अन्य निःशुल्क जांच की गई। साथ ही दवाएं भी वितरित की गई। महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से आयोजित शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण, महापौर शैलेंद्र सिंह रावत व भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। विस अध्यक्ष ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना है। शिविर में लोगों को कैंसर सहित अन्य बीमारियों से बचाव की जानकारी दी गई। महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के डा. शहनवाज ने कैंसर के कारणों व उससे बचाव की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। शिविर में लोगों की खून सहित अन्य जांच भी की गई। इस मौके पर रमा हिंदवाण, सविता डबराल, धीरेंद्र मोहन रतूड़ी, दिनेश नेगी, प्रवेश कुमार बड़ोला, गिरीश उनियाल, राजकुमार, डा. नितिन बडेवाल, डा. आकांक्षा अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

भालू के डर से ग्रामीणों ने झाड़ियां साफ की

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : विकासखंड कल्जीखाल क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डांगी गांव में मंगलवार को अभियान चलाकर मुख्य मार्गो सहित विद्यालय जाने वाले मार्गो की झाड़ियों को काटकर सफाई की। बता दें कि विगत शुक्रवार को छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाते समय रास्ते में भालू दो शावकों संग देखा गया था। इसके अलावा गांव कई दिनों से गुलदार की भी सक्रियता बनी हुई। मंगलवार को समाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी, पूर्व प्रधान भगवान सिंह चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजू रावत, महिला मंगल दल अध्यक्ष नीतू लिंगवाल की नेतृत्व में अभियान चलाकर गांव के मुख्य संपर्को मार्गो एवं विद्यालय जाने वाले संपर्क रास्तों की झाड़ियां काटी गई। वहीं पूर्वी मनियारस्यूं ग्राम पंचायत डांगी की नव निर्वाचित प्रधान बबीता देवी के नेतृत्व में डांगू एवं हसुडी गांव में महिलाओं ने शहीद नरेश रावत मोटर मार्ग से गांवों तक संपर्क मार्गो की अभियान चलाकर झाड़ियां काटी गई। ग्रामीणों ने बताया कि रास्तों दोनों तरफ उगी झाड़ियां भी खतरे का कारण बन रही हैं। इससे रात्रि में जंगली जानवरों की ओर से हमला होने का भय रहता है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान पूजा देवी, पूर्व प्रधान विमला देवी सहित अन्य ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही।

कल्जीखाल में जल्द तैनात होगी फॉरेस्ट टीम

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : कल्जीखाल ब्लाक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल डांगी में पढ़ने जा रहे बच्चों को स्कूल आवाजाही के समय रास्ते में भालू दिखाई देने के मामले में वन विभाग भी हरकत में आया है। वन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए विभागीय टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों ने रूट प्लान तैयार करने के आदेश दिये है। बता दें कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल डांगी में डांगी और थनूल गांव के तीन-तीन बच्चे पढ़ने आते है। गांव से स्कूल जाते वाले रास्ते में झांडियां होने की वजह से बच्चों को आए दिन वन्य जीवों का खतरा बना रहता है। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया है कि कल्जीखाल ब्लाक के इस स्कूल को लेकर विभागीय टीम को भी रूट प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। बताया कि खासकर उस समय पर ज्यादा फोकस किया जाए जिस समय बच्चे सुबह स्कूल जाते है और फिर उसी रास्ते वापस घर आते हैं। इस बीच बच्चों ने स्कूल जाने वाले रास्ते में भालू देखा था तब से बच्चों को भालू का डर बना हुआ है। इसलिए वह स्कूल जाते समय साथ में बाजा और स्कूल का डरम बजाकर जाते है, ताकि रास्ते में किसी तरह का खतरा न रहे। कल्जीखाल के खंड शिक्षाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा पहले है। इसलिए स्कूल को गांव के पंचायत भवन पर संचालन को लेकर अभिभावक की भी राय ली जा रही है। यदि राय बन जाती है तो स्कूल का संचालन सुरक्षित स्थान पर हालात सामान्य होने तक किया जा सकता है।

दिवाकर भट्ट के योगदान को किया याद

आयोजित बैठक में अपने विचार रखते वक्ता

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : नागरिक मंच ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व पूर्व काबीना मंत्री दिवाकर भट्ट के योगदान को याद किया। कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए किया गया उनका संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान दो मिनट मौन का धारण कर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई।

बैठक में नागरिक मंच के साथ ही अन्य संगठन के लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि दशकों पूर्व जब उत्तराखंड राज्य गठन की रणनीति तैयार की गई तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका दिवाकर भट्ट निभाई।

दिवाकर भट्ट ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई बार अनशन किया। आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में दिवाकर भट्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। कहा कि दिवाकर भट्ट का चला जाना हम सभी के लिए बड़ी क्षति है। शोक व्यक्त करने वालों में महेंद्र रावत, आरपी पंत, प्रवेश नवानी, जयदीपक रावत, चित्रमणी देवलियाल, उमेद भंडारी, कैलाश थलेडी, राकेश लखेड़ा, अतुल भट्ट, भरत मोहन, बिजेंद्र उनियाल, दिनेश पोखरियाल, शिवप्रसाद कुकरेती, कुलदीप असवाल, सुरेंद्र भाटिया, एसएन पांडेय, शंकर गौड़ सहित अन्य मौजूद रहे।

आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएं

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आत्मनिर्भर भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे इसके लिए हमें गंभीरता से कार्य करना चाहिए। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे विपुल मैंदोली का कार्यकर्त्ताओं ने कौड़िया बैरियर पर स्वागत किया। कौड़िया बैरियर से बाइक रैली के साथ कार्यकर्त्ताओं का हुजूम नगर निगम प्रेक्षागृह पहुंचा। प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में प्रदेश अध्यक्ष विपुल मैंदोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में युवा शक्ति सबसे प्रभावी माध्यम है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने की सबसे मजबूत नींव आज की युवा शक्ति है। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का आह्वान किया। कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत, नवाचार, स्थानीय उत्पादों के सम्मान और स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के अभियान से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को घर-घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल ने कहा कि भारत विश्व के सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाला देश है और यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं तकनीकी रूप से दक्ष और प्रतिभाशाली युवाओं को देश के विकास में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के विचार को हम हर नागरिक तक पहुंचाने के साथ ही प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप एक विकसित, सशक्त और गौरवशाली भारत के निर्माण में अपनी पूर्ण भागीदारी देने का आह्वान किया। इस अवसर पर महापौर शैलेंद्र सिंह रावत, जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह नेगी, विजयानंद पोखरियाल, हरी सिंह पुंडीर, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह आर्य, जिला मंत्री यमन डबराल, नगर अध्यक्ष विकासदीप मित्तल, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सौरव नौडियाल, पार्षद रजनीश बेबनी, नीरू बाला खंतवाल, ऋतु चमोली, अमित नेगी, भाबर मंडल अध्यक्ष आशीष रावत सहित तमाम कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

मंत्री ने बूंखाल मेले की तैयारियों की ली जानकारी

श्रीनगर गढ़वाल : कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को श्रीनगर विधानसभा के पांचों मंडलों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली।

बैठक में उन्होंने आगामी 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले बूंखाल मेले की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पौड़ी के थलीसैंण विकासखंड के बूंखाल में कालिंका माता मंदिर में लगने वाला बूंखाल मेला लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया कि इस बार मेले में लगभग 25 हजार श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। साथ ही पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से मेले को दिव्य और भव्य बनाने में सहयोग करने की अपील की। डॉ. रावत ने कहा कि कंडारस्यू पेयजल योजना का पानी अगले तीन माह में शुरू कर दिया जाएगा। वहीं डूंगरीपंथ-खेड़ाखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन भी शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों को प्रत्येक मंडल के अंतर्गत सभी बूथों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन भी जरूरतमंद परिवार को आवास, राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड लंबित रह गये उन्हें पूर्ण सहयोग देने को कहा है। इस मौके पर जिला महामंत्री गणेश भट्ट, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, खिर्सू मंडल अध्यक्ष मीना गैरोला, थलीसैंण मंडल अध्यक्ष आनंद नेगी आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

मूल निवासियों को नौकरी में आरक्षण देने की मांग

श्रीनगर गढ़वाल : उत्तराखंड निवासियों के लिए मूल निवास, भू-कानून एवं शिक्षित गरीब युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर समाजसेवी पृथ्वी बिष्ट ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में पृथ्वी बिष्ट ने उत्तराखंड राज्य के मूल निवासियों को नौकरी में 85 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने, लोकपाल बिल लागू किए जाने, भू-कानून लागू किए जाने सहित गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की मांग की है। (एजेंसी)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रवीन दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के समस्त अभिलेखों में मेरा नाम प्रवीन कुमार दर्ज है। अतः मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम प्रवीन कुमार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पता- प्रवीन कुमार पुत्र श्री दीपचन्द नन्दपुर, निकट गणेश चौक, वार्ड नं0 30 नन्दपुर, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(1525/21)

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से, उप मुख्य अभियन्ता / निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के तहत खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:

1	कार्य का नाम व स्थान	उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के कार्य क्षेत्र में मुरादाबाद मंडल के लखनऊ-मुरादाबाद सेक्शन पर मुरादाबाद स्टेशन यार्ड में किमी 1397/18-20 पर मौजूदा जीर्ण-शीर्ण आरओबी संख्या 1142-ए (02-लेन) को ध्वस्त करने के बाद, नए आरओबी (स्पैन 1x76.000 मीटर सी/सी एक्सप. जॉइंट (बो स्ट्रिंग गर्डर) + 2x16.710 मीटर सी/सी एक्सप. जॉइंट (पीएससी गर्डर)) के निर्माण के संबंध में।
2	कार्य पूरा करने की अवधि	12 (बारह) माह
3	कार्य की अनुमानित लागत	रु. 2137.71 लाख
4	जमा की जाने वाली जमानत राशि	रु. 12,18,900.00
5	निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की वृहत जानकारी	ई-निविदा प्रपत्र की वृहत सूचना उत्तर रेलवे कि वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपर्युक्त निविदा प्रपत्र आईआरईपीएस की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर दिनांक 02.12.2025 से दिनांक 24.12.2025 को 11:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उपर्युक्त टेण्डर के सम्बन्ध में अन्य सभी नियम व शर्तें टेण्डर डॉक्यूमेंट में दी गई हैं। निविदा सूचना कि वृहत जानकारी कार्यालय में निविदा सूचना बोर्ड से की जा सकती है।
6	अन्तिम तिथि/ई-निविदा अपलोड करने की तिथि	24.12.2025 को 11:30 बजे तक। ई-निविदा दिनांक 10.12.2025 से 24.12.2025 को 11:30 बजे तक आईआरईपीएस की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।
7	ई-निविदा खुलने की तिथि व समय	टेक्निकल सह कमर्शियल बिड दिनांक 24.12.2025 को 11:30 बजे तक ई-टेण्डर अपलोडिंग बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जाएगी। योग्य टेंडरर की फाइनेंशियल बिड कार्यालय द्वारा दी गई दिनांक व समय की सूचना के आधार पर बाद में खोली जाएगी।

निविदा सूचना सं. 1-डब्लू-टेण्डर-293-उप मु.अभि. नि. मुरादाबाद दिनांक- 02.12.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3727/25

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रवर मण्डल अभियन्ता/II/मुरादाबाद द्वारा ई-टैण्डर निम्न टैंडर संख्या के अंतर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की कीमत तथा धरोहर राशि का भुगतान निविदादाता द्वारा केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चैक डिपोजिट रसीद आदि स्वीकार्य नहीं होंगे। टैंडर से संबंधित अन्य जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें।

टैंडर संख्या / दिनांक	247-DRM-MB-25-26 Date: 02.12.2025
कार्य का नाम	Heavy repair to pf surface, duty hut, staff quarter, colony road, white washing and other misc work under ADEN/I/HRI
टैंडर क्लोजिंग दिनांक / समय	26.12.2025 at 16:00
अनुमानित लागत(रु)	₹89,94,733.77
धरोहर राशि(रु)	₹1,79,900/-
बिडिंग स्टार्ट तिथि	12.12.2025
ऑफर की वैधता	60 दिन
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह

No. 74-W/3/3/WA/Publication Dated: 02.12.2025 3733/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

संक्षिप्त समाचार

तहसील दिवस में 58 शिकायत दर्ज, दो का निस्तारण

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : बीरोंखाल तहसील दिवस एवं ब्लाक स्तरीय बहुद्देशीय शिविर में मंगलवार को क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा 58 शिकायतें दर्ज कराई गई। दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण करने के लिए एडीएम पौड़ी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में मिली शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लेकर शीघ्र हल करें।

मंगलवार को बीरोंखाल स्यूंसी में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाए। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा 2 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिए और दो प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया। स्वास्थ्य विभाग ने 98 मरीजों की जांच की, जबकि उद्यान, कृषि, पशुपालन विभाग ने किसानों व पशुपालकों को बीज, उपकरण और दवाइयां वितरित की। खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, ब्लाक, स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टाल लगाए गए। इस अवसर पर जेष्ट प्रमुख कुलदीप सिंह नेगी, एसडीएम श्रेष्ठ गुनसोला, तहसीदार शंकर सिंह, बीडीओ सुर्दशन सिहं बुटोला, राय सिंह नेगी, एडीओ पंचायत राजेन्द्र रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष ओमपाल बिष्ट, सीएचसी प्रभारी शैलेन्द्र रावत, पशु धन प्रसार अधिकारी हरीश गौनियाल आदि मौजूद थे।

13वां स्थापना दिवस नौ दिसंबर को

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : वरिष्ठ नागरिक संगठन की ओर से संगठन का 13वां स्थापना दिवस नौ दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए संगठन के सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष पीएल खंतवाल, महासचिव रिपुदमन सिंह बिष्ट ने बताया कि कार्यक्रम नजीबाबाद रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता विभाग के महानिदेशक डा. मनोज कुमार व विशिष्ट अतिथि डा. सुषमा थलेड़ी होगी। बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के दो खिलाड़ियों, संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन वरिष्ठ नागरिकों व दानवीर को स्व. सुरेंद्र सिंह नेगी स्मृति सम्मान दिया जाएगा।

सांसद बलूनी का जन्मदिन मनाया

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंदन नगर पालिका श्रीनगर में सामाजिक भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को अध्ययन व खाद्य सामग्री वितरित की। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक आयुष मियां, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित रावत, वींरेंद्र बिष्ट, हिमांशु भंडारी, अमन सागर, करन परिहार, वरुण शर्मा, विपिन दानू, दीप्ति आर्य, दीक्षा, काजल, वंदना, अरविंद आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

महिला अपराधों पर आयोग सख्त, पुलिस को दिए कड़े निर्देश

देहरादून। राज्य के अलग अलग इलाकों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर महिला आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने कुछ मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं। चकराता क्षेत्र में गर्भवती महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आने पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले को राजस्व पुलिस से तुरंत रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने जिलाधिकारी और एसपी देहात को त्वरित व कठोर कार्रवाई करने को कहा। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला कि अस्मिता पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता की सुरक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। आयोग ने पूरे मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। वहीं बेरीनाग महाविद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपों और आरोपी प्राध्यापक का वीडियो वायरल होने के बाद भी आयोग ने तत्काल कार्रवाई को कहा है।

रुद्रप्रयाग के दो शिक्षकों ने उत्कृष्ट खेल दिखाकर जीते मेडल

रुद्रप्रयाग। देवभूमि उत्तराखंड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जनपद रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष अजय प्रकाश चौधरी ने 45 से अधिक आयुवर्ग में 500 मीटर वॉल रेस में रजत पदक हासिल किया। जबकि चक्का फेंक और हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई।

तहसील दिवस में डीएम ने सुनी 50 समस्याएं

डीएम की अध्यक्षता में जिलासू तहसील में आयोजित हुआ तहसील दिवस

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : मंगलवार को तहसील जिलासू में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि अधिकारी शिकायतों का तेजी से निस्तारण करें और किसी कारणवश समाधान न होने पर शिकायतकर्ता को उसका कारण अवश्य बताएं। तहसील दिवस में मुख्य रूप से सड़क, पेयजल, बिजली, श्रम कार्ड, राशन कार्ड, मार्ग सुधार, बंदर-लंगूर एवं जंगली सूअरों से फसलों को हो रहे नुकसान संबंधी समस्याएं दर्ज कराई गईं।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अधिकारियों को सड़क, बिजली, पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को झूलते विद्युत तारों को तत्काल सुधारने, विद्युत आपूर्ति की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को बंदर, लंगूर, जंगली सूअर एवं भालू से ग्रामीणों को हो रही समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़कों के निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पेयजल समस्याओं के त्वरित निस्तारण और रेलवे द्वारा अधिकृत भूमि के मुआवजे से संबंधित प्रकरणों का निरीक्षण कर समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर परियोजना निदेशक आनन्द सिंह भकुनी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता, एसडीएम सोहन सिंह रांगण, पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेन्द्र सिंह राणा, मुख्य शिक्षाधिकारी श्रीकांत पुरोहित सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

मेधावी छात्र गणेश का किया गया जोरदार स्वागत

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पीएम श्री आदर्श उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बल्ली में मंगलवार को मेधावी छात्र गणेश का भव्य स्वागत किया गया। गणेश ने राज्य स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गणेश की सफलता पर क्षेत्र मंगलवार को विद्यालय परिसर में स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर आए छात्र गणेश का स्वागत किया। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ऋषि कंडवाल ने छात्र को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यमंत्री ऋषि कंडवाल ने कहा कि गणेश ने राज्य स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं विद्यालय का नाम रोशन किया। कहा कि विद्यालय के छात्र-छात्राओं को उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कहा कि सकारात्मक सोच और मेहनत से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। सभी छात्र-छात्राएं अपने लक्ष्य को हासिल कर विद्यालय, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन पूर्व कनिष्ठ प्रमुख जगदीश प्रसाद बेबनी ने किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रमिला बलूनी, ज्येष्ठ प्रमुख सुनील नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य जयपाल सिंह, प्रधान बल्ली रंजनी देवी, प्रधान चंडी प्रसाद कुकरेती, रामप्यारी देवी, प्रधानाचार्य युगजीत चंद्र सेमवाल आदि मौजूद थे।

जिले के पांच दिव्यांगजों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विश्व दिव्यांग दिवस पर पौड़ी जिले के पांच दिव्यांगजनों को सम्मानित किया जाएगा। इस साल जिले से 5 दिव्यांगजन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित हुए हैं। जिसमें दो दक्ष दिव्यांग कर्मचारी और तीन स्वयं-रोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित कर रहे दिव्यांगजन शामिल हैं। 3 दिसबंर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्य सरकार द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, स्वयं रोजगार में संलग्न दिव्यांग व्यक्तियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ियों, सेवा-योजकों व प्लेसमेंट अधिकारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पौड़ी के अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने बताया कि दो दक्ष दिव्यांग कर्मचारी और तीन स्वयं-रोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जित कर रहे दिव्यांगजन इसमें शामिल हैं। चयनित दिव्यांग कर्मचारियों में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रक्षा नेगी और पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी मनीष रावत हैं। रक्षा नेगी अपनी प्रशासनिक दक्षता, समयबद्ध कार्य-संयोजन और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। वहीं मनीष रावत ने ग्राम्य क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं को मजबूत बनाने, किसानों के साथ निरंतर संवाद कायम रखने और तकनीकी सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाई। स्व-रोजगार श्रेणी में चयनित सूरज कुमार, दीपक और शुभम जोशी ने सीमित संसाधनों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपने दम पर आजीविका के मजबूत स्रोत विकसित किए हैं। बीरोंखाल ब्लाक के ग्राम कसाणी निवासी सूरज कुमार ने सीएससी सेंटर संचालन, डिजिटल सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित काम को रोजगार का जरिया बनाया है। तहसील पौड़ी के ग्राम काण्डई के दीपक ने बकरी पालन को योजनाबद्ध ढंग से विकसित कर इसे सफल व्यवसाय का रूप दिया। वहीं ग्राम कसाणी के ही शुभम जोशी ने फैब्रिकेशन कार्य को अपने कौशल और मेहनत के बल पर आजीविका का आधार बनाया है और दूसरों के लिए प्रेरणा बने है।

सम्मान से मिलता है कर्तव्य-निर्वहन में उत्साह

सम्मान की सूचना पर मनीष रावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें न केवल कार्यस्थल पर ऊर्जा बढ़ाती हैं, बल्कि कर्तव्य-निर्वहन में उत्साह और मानसिक संतोष भी होता है। इस प्रकार का सम्मान समाज में दिव्यांगजन की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाता है।

यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजी गई मीनाक्षी

नई टिहरी। एचएनबी गढ़वाल विवि के एसआरटी परिसर बादशाहीथौल के वनस्पति विज्ञान विभाग की शोध छात्रा मीनाक्षी रावत को देहादून में संपन्न हुए उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड से नवाजा गया है। जिस पर परिसर प्रशासन ने उन्हें बधाई दी है। 28 से 30 नवम्बर तक देहरादून के ग्राफिक एरा विवि में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन का यूकॉस्ट ने आयोजन किया था। जिसमें देश–विदेश के अनेक वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण के लिए एसआरटी परिसर के शोध छात्रा मीनाक्षी को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह और यू–कॉस्ट के डीजी प्रो. दुर्गेश पंत, आयोजक सचिव डॉ. डीपी उनियाल ने उन्हें यह सम्मान दिया। मीनाक्षी को पूर्व में भी विभिन्न सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्तमान में वह वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. एलआर डंगवाल के निर्देशन में वीड्स एवं मिलेट्स पर शोध कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शोध पत्र भी उनके प्रकाशित हो चुके हैं।

डीएम ने किया आंगनबाड़ी केंद्र व प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ग्राम सभा गिरसा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम क्षेत्र में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने विकासखंड पोखरी के हणज में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र एवं प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में प्रकाश व्यवस्था उचित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को शीघ्र आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्मित आवासों की गुणवत्ता का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम क्षेत्र में

सिंचाई सुविधा हेतु बन रही नहर प्रणाली का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिनके समाधान हेतु उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर परियोजना निदेशक आनन्द सिंह भकुनी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता, एसडीएम सोहन सिंह रांगण, मुख्य शिक्षाधिकारी श्रीकांत पुरोहित सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज निर्माण निर्णायक चरण में

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के बाद उत्तराखंड में मेडिकल एजुकेशन का विस्तार अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ चुका है। राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ रही है और उसी अभियान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है सीमांत पिथौरागढ़।

कठिन भूगोल और सीमित संसाधनों के बावजूद यहां राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब यह परियोजना अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। मेडिकल कॉलेज परिसर अब लगभग पूरा आकार ले चुका है। विशाल इमारतें, सुव्यवस्थित ब्लॉक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर-यह सब पिथौरागढ़ को पहाड़ का एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनाने की दिशा में बड़े कदम साबित हो रहे हैं। स्थानीय जनता इस परियोजना को लेकर काफी उत्साहित है। लोगों की मानें तो मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हल्द्वानी, देहरादून या बाहरी राज्यों की ओर जाने की मजबूरी खत्म होगी। रोजगार, व्यवसाय और आवागमन के नए अवसर भी जिले में उभरेंगे। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अगर निर्माण की यही गति बनी रही तो यह लक्ष्य समय पर पूरा होता नजर आ रहा है। पेयजल निगम की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट बताती है कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के अधिकांश प्रमुख ब्लॉक 70 से 95 प्रतिशत तक पूरे हो चुके हैं। यह न केवल विभाग की कार्यकुशलता का प्रमाण है, बल्कि सीमांत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का भविष्य भी उज्जवल होने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फैकल्टी ब्लॉक, लैबोरेट्री ब्लॉक और परीक्षा-लेक्चर थिएटर ब्लॉक 65 से 80 प्रतिशत तक बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन भवनों के लगभग तैयार हो जाने से आने वाले दिनों में फैकल्टी नियुक्ति, विभागों की स्थापना और शैक्षणिक सत्र शुरू करने की दिशा में बड़ा रास्ता साफ होगा।

हॉस्टल भवों का निर्माण कार्य सबसे तेज

हॉस्टल भवनों में निर्माण कार्य सबसे तेज रहा है। बॉयज हॉस्टल 90 प्रतिशत और गर्ल्स हॉस्टल 80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। गर्ल्स डाइनिंग ब्लॉक 78 प्रतिशत और बॉयज डाइनिंग 35 प्रतिशत निर्माण स्तर पर है। वहीं आवासीय ब्लॉकों में टाइप–6 और टाइप–4 श्रेणियां 85 से 96 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी हैं। यह पूरी संरचना मेडिकल कॉलेज के संचालन को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे डॉक्टरों, नर्सों, फैकल्टी और छात्रों को बेहतर रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अस्पताल परिसर में भी प्रगति उल्लेखनीय है। इमरजेंसी ब्लॉक रिमॉडलिंग 90 प्रतिशत और आईपीडी–1 में 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। ओपीडी–2 में 35 प्रतिशत, जूनियर रेजिडेंट हॉस्टल में 20 प्रतिशत, और इंटर्न होस्टल में 25–65 प्रतिशत में काम जारी है। कुछ नए ब्लॉक जैसे आईपीडी–2, आईपीडी–3, नर्स हॉस्टल, बीएमडब्लू ब्लॉक और मोर्चरी अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि जल्द ही इनके निर्माण में भी तेजी आएगी।

अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है। सीमांत जिले में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। अधिकांश प्रमुख ब्लॉकों में तेज प्रगति हुई है और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेसियों ने शराब के ठेके के सामने दिया सांकेतिक धरना

नई टिहरी। राजमार्ग से सरकारी शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ठेके के समक्ष सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेसी बोले यदि शराब के ठेके को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। मंगलवार दोपहर में कांग्रेसियों ने सरकारी शराब के ठेके के समक्ष सांकेतिक धरना देते हुए कहा कि शराब का ठेका राजमार्ग पर खोला गया है। जिससे राजमार्ग जाम रहने के साथ ही यहां पर एक्सीडेंटल जोन बन गया है। बीते सोमवार को यहां पर एक वाहन ने कई वाहनों का टक्कर मारी दी।

ठेके के सामने राजमार्ग पर जाम के कारण कई बार दुर्घटनायें हो रही हैं। कभी बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राजमार्ग पर ठेका मानकों के विपरीत खुला है। जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। जबकि प्रदेश सरकार मात्र मुनाफे के चलते आम लोगों की परेशानियों को नहीं देख रही है। सरकार लोक कल्याण के बजाय शराब बेचने में मशगूल नजर आ रही है। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल खंडवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप पंवार, देवेंद्र नौडियाल सहित दर्जनों मौजूद रहे।

आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का मांगों को लेकर सचिवालय कूच

– पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समर्थन

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने राज्य कर्मचारी घोषित करने, ग्रेज्युटी, पेंशन भविष्य निधि और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरने में पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। सोमवार को उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री के नेतृत्व में प्रदेशभर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका ने परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास अपने काम के अतिरिक्त बीएलओ का भी काम है। काम अधिक होने के बाद भी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत कम है। उनके मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए। चूना भट्ठा निवासी कुसुम ने बताया कि 15 साल से सहायिका के पद पर काम कर रहीं हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्हें केवल 5 हजार मानदेय दिया जाता है। समय के साथ उनपर जिम्मेदारियां तो बढ़ी है लेकिन मानदेय इतना ही बढ़ सका है। उन्होंने बताया कि भवन किराया के लिए सरकार की ओर से हजार रूपए दिए जाते हैं।

मेडिकल कालेज के नाम पर किया जा रहा गुमराहः खंडवाल

नई टिहरी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल खंडवाल ने कहा कि टिहरी में मेडिकल कालेज खोलने के नाम पर यहां की जनता को प्रदेश सरकार व क्षेत्रीय विधायक गुमराह कर रहे हैं। बीते कई सालों से मेडिकल कालेज की बात की जा रही है। लेकिन नहीं मेडिकल कालेज के लिए बजट जारी किया गया है, नहीं कोई शासनादेश। जिला कांग्रेस कार्यालय में खंडवाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज टिहरी में न बनाने पर कांग्रेस आंदोलन को मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कालेज को लेकर स्पष्ट घोषणा करे। टिहरी झील में आयोजित हुए वाटर स्पोर्टस कप सीएम के समक्ष मेडिकल कालेज की बातें स्थानीय विधायक ने उठाई, लेकिन इसे लेकर सीएम ने काई स्पष्ट बात नहीं कही, जिससे साफ जाहिर है कि प्रदेश सरकार टिहरी में मेडिकल कालेज के नाम पर गुमराह कर रही है। कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं व महिलाओं के साथ भी छलावा कर रही है। बेरोजगारी के कारण आज युवा बेहाल है। प्रदेश सरकार 9 साल के कार्यकाल में मात्र 22 हजार युवाओं को रोजगार देने का दावा भर कर रही है। जबकि तत्कालीन सीएम हरीश रावत के कार्यकाल मे 32 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया था।

घनसाली की स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से उपेक्षा का शिकारः बॉबी पंवार

नई टिहरी। घनसाली क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के धरना–प्रदर्शन को लगातार जनसमर्थन मिलता जा रहा है। बुधवार को आंदोलन के 37वें दिन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार धरना स्थल पहुंचे और मोर्चा की मांगों का पूर्ण समर्थन किया। बुधवार को पीएचसी पिलखी में धरना स्थल पर पहुंचे बॉबी पंवार ने कहा कि, घनसाली क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रही हैं, जिसके चलते आम जनता को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि वह सरकार तक इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। धरना स्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि, घनसाली क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी, उपकरणों का अभाव और स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर स्थिति पहले से ही चिंता का विषय रही है।

ड्रग्स के विरुद्ध जिला प्रशासन का एक्शन जारी

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार व विद्यार्थियों में बढती नशे की प्रवृत्ति पर सख्त रुख अपनाते हुए जिले में स्थित सभी शैक्षित संस्थानों में रोस्टरवार अभियान चलाते हुए टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि के नेतृत्व में आज दूसरे दिन भी ग्राफिकएरा डीम्ड यूनिवर्सिटी 150 छात्र/छात्रओं की रेंडम सैम्पलिंग की गई। वहीं जिलाधिकारी के सख्त निर्देश है कि यदि किसी स्कूल कालेज में ड्रग टेस्टिंग में कोई विद्यार्थी, बच्चे पासिटिव पाए जाते हैं तो सम्बन्धित डीन, कालेज स्वामी के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के नशामुक्त राज्य के विजन को धरातल पर उतारने को जिला प्रशासन ने बड़े व कड़े

कदम उठाते हुए विद्यार्थियों / किशोंरो को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने कमर ली है।

जिलाधिकारी ने कहा कि ड्रग टैस्टिंग से छात्र/छात्राओं और अभिभावकों से न घबराने का अनुरोध किया तथा इस ड्राईव में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की हैं। उन्होंने कहा कि इस ड्राईव का उद्देश्य स्कूल, कालेज में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाना तथा नशामुक्त समाज बनाना है। जिले के सभी निजी एवं शासकीय सभी शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटी में स्कूल के एक छात्र और एक छात्रा को शामिल कर कमेटी को सक्रिय करने, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना देने हेतु शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बैनर / पोस्टर के माध्यम से मानस हेल्पलाइन नंबर 1933, एनसीवी मानस पोटर्ल और डिस्ट्रिक्ट डी–एडिक्शन सेंटर हेल्पलाइन नंबर 9625777399 का पोस्टर सभी कार्यालयों में चस्पा कराते हुए इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने और हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा रायवाला में ओल्ड एज होम में 30 बैडेड नशामुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। योजनाओं की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखे। जिन योजनाओं पर 80 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, उनको प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराते हुए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने

डीपीआरओ को निर्देश दिए कि विवाद के कारण जिन गांवों में योजनाएं लंबित है, उन गांव में प्रधान से स्वयं वार्ता करें और विवाद को दूर कराते हुए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाए। डीडब्लूएसएम और एसडब्लूएसएम में योजनाओं को ऑनलाइन करने हेतु सभी डिवीजन डाटा दें।

मुख्य विकास अधिकारी ने हर घर जल सर्टीफिकेशन कायी में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में नल जल मित्र की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कार्य पूरा करने को कहा। नल जल मित्रों को जल गुणवत्ता परीक्षण किट का प्रयोग सिखाते हुए नियमित रूप से पानी की जांच सुनिश्चित की जाए। नल जल मित्रों को समुदाय से पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था कराई जाए। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और नल जल मित्र के बीच समन्वय बनाया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ऐसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र एवं पंचायत भवन जिसमें अभी तक जल संयोजन नहीं हुआ है, शिक्षा अधिकारी एवं डीपीआरओ उनकी सूची तत्काल उपलब्ध करें। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नही की जाएगी।

नंदा गौरा के लिए आवेदन अब 20 दिसंबर तक

नई टिहरी। नंदा गौरा योजना के लिए अब 20 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देशों के क्रम में विभाग ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। सूचना विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आदेश के तहत इस योजना में जनपद टिहरी गढ़वाल में भी अब अंतिक तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 20 दिसंबर कर दी है। कन्या जन्म के आधार पर योजना का लाभ लेने और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक पूरे प्रदेश में 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जन मिलन कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश में कई जगह लोगों ने बताया कि पात्र होने के बाद बाद भी विभिन्न वजहों से अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
—सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com